

[illegible]

आस्था के नाम पर व्यापार- 21 हजार में धर्मिक विशेषाधिकार, श्रद्धालुओं में आक्रोश

कोरबा में शिव महापुराण कथा आयोजन विवादों में, गरीबों से चंदा लेकर किया गया भेदभाव



कोरबा अम्बिकावाणी - जिले में श्रद्धा और भक्ति से जुड़ी शिव महापुराण कथा इस बार विवादों के घेरे में आ गई। विख्यात कथा वाचक पं. प्रदीप मिश्रा की सात दिवसीय कथा (१२ से १८ जुलाई) को लेकर श्री महाकाल भक्त मंडल समिति कोरबा वर गंभीर आरोप लगे हैं। आयोजन में कथित रूप से २१,००० रुपये में विशेष पास बेचे गए, जिससे आस्था रखने वाले हजारों श्रद्धालुओं में

गहरी नाराजगी है। वायरल ऑडियो क्लिप में समिति के कोषाध्यक्ष शैलेश शुक्ला के रिश्तेदार की आवाज बताई जा रही है, जिसमें वह कहते हैं 'इस २१ हजार दर, पास लो, सामने बैठो। इस खुलासे के बाद श्रद्धालुओं में यह भावना गहराई है कि भक्ति अब अमीरों के लिए आरक्षित कर दी गई है। बदलते आयोजन स्थल और सीमित प्रवेश ने बड़ाई खेची



पहले ही आयोजन स्थल को लेकर कई बार परिवर्तन हुआ। अंततः टांसपोर्ट नगर स्थित मीरा रिसॉर्ट परिसर में यह आयोजन तय हुआ, जहां प्रतिदिन केवल ३०० श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति है। सीमित व्यवस्था के बीच २१ हजार रुपये में विशेष पास देकर सामने बैठने की सुविधा ने विवाद को और हवा दी है। गरीब श्रद्धालुओं की व्याथा इस कथा भक्ति भी बिकाऊ हो गई? सीताबाई वर्मा, निवासी दरौ, ने कहा - हम रोज कथा सुनने की उम्मीद में आते हैं, लेकिन जब सुना कि सामने बैठने के लिए पैसे लगते हैं, तो दिल टूट गया।

क्या हमारी आस्था अब अमीरी-गरीबी देखेगी? कमला तिवारी ने कहा - सुबह से कतार में लगते हैं, फिर भी कहते हैं 'इस पास नहीं है। अगर पैसे से ही धर्म के दरवाजे खुलें, तो आम श्रद्धालु क्या करें? एक स्वयंसेवक ने बताया कि उन्होंने प्रचार, साज-सज्जा और चंदा देने में सहयोग किया, लेकिन अब उन्हें बाहर खड़ा किया गया। उनका सवाल इस कथा वाचक की भक्ति का क्या यह भक्ति है या धंधा? धर्म और पैसे का गठजोड़ - उठी जवाबदेही की मांग इस घटनाक्रम ने धार्मिक आयोजनों की पारदर्शिता और नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिलेभर में यह मांग उठ रही है कि श्री महाकाल भक्त मंडल समिति को सार्वजनिक रूप से इस प्रकरण पर जवाब देना चाहिए, ताकि भविष्य में जब आयोजन समिति के मोबाइल नंबर ६२६३८१९०८६ पर संपर्क किया गया, तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि २१ हजार रुपये में पास दिए गए हैं। इससे वह सिद्ध हो गया कि आयोजन में आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया गया है।

भारतमाला फोरलेन की गुणवत्ता पर उठे सवाल- कोरबा में निर्माणधीन मार्ग पहली ही बारिश में टूटा

जनता बोली - यह ढाँटाचार का खुला उदाहरण

कोरबा अम्बिकावाणी - जिले में भारतमाला परियोजना के तहत बन रही बहुउद्देशीय फोरलेन सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में हुई पहली ही बारिश में तरल मुख्य मार्ग पर निर्माणधीन सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क पूरी तरह तैरा भी नहीं हुई थी, लेकिन टूट-फूट ने निर्माण कार्य को पारदर्शिता और गुणवत्ता पर गहरे प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।

स्थानीय नागरिकों ने इसे खुला ढाँटाचार करार देते हुए कहा कि करोड़ों रुपये की इस परियोजना में घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है। सोशल मीडिया पर क्षतिग्रस्त सड़क का वीडियो वायरल हो रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग सवाल उठा रहे हैं 'इस जब सड़क चालू ही नहीं हुई, तब ही यह बंधू टूट तो एक साल भी कैसे टिकेगी?

निर्माण एजेंसी पर लापरवाही के आरोप ग्रामीणों और स्थानीय संघटनों ने निर्माण एजेंसी तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि कार्य गुणवत्ता जांची नहीं गई, न ही निगरानी की कोई प्रणाली व्यवस्था है। यदि अब सुधार नहीं हुआ तो भविष्य में यह किसी गंभीर हादसे का कारण बन सकता है।

अन्य समस्याएं भी बढ़ीं चापा मुख्य मार्ग सहित कई स्थानों पर भूमि अधिग्रहण में देरी, आवाज न मिलना, क्लर और टैफिक जाम जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं, जो बारिश में और बिगड़ रही हैं।

प्रशासन से अपील स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि निर्माण की जांच दोषियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसे ढाँटाचार को रोका जा सके।



छत्तीसगढ़ में वैकल्पिक उर्वरकों की कोई कमी नहीं

रायपुर। राज्य में खरीफ सीजन 2025 के दौरान विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की मांग को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने समय रहते न सिर्फ इसकी ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की बल्कि रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति भंडारण एवं वितरण व्यवस्था पर भी लगातार निगरानी रख रही है, जिसके चलते राज्य में रासायनिक उर्वरकों के भंडारण एवं उठाव की स्थिति बेहतर बन गई है। डी.ए.पी. की कमी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एन.पी.के., सुपर फॉस्फेट और नैने डी.ए.पी. जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को उपलब्धता सुनिश्चित कर किसानों के हितों का ध्यान रखा है। छत्तीसगढ़ में अब तक विभिन्न प्रकार के 12.27 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण कर लिया गया है, जिससे खरीफ सीजन में किसानों को समय पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध हो सके। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ 2025 में पूर्व में कुल 14.62 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित था। इसमें यूरिया 7.12



लाख, डी.ए.पी. 3.10 लाख, एन.पी.के. 1.80 लाख, पोटाश 60 हजार तथा सुपर फॉस्फेट 2 लाख मीट्रिक टन शामिल हैं। वर्तमान में कुल 12.27 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण किया जा चुका है। डी.ए.पी. की आपूर्ति में कमी के चलते उर्वरक वितरण के लक्ष्य को संशोधित कर अन्य वैकल्पिक उर्वरकों जैसे- एन.पी.के., एएसएफ के लक्ष्य में 4.62 लाख मीट्रिक टन को उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसके चलते खरीफ सीजन 2025 में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की वितरण का लक्ष्य 17.18 लाख मीट्रिक टन हो गया है। राज्य में अब तक 5.63 लाख

चरणबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। डी.ए.पी. के आयात में राष्ट्रीय स्तर पर कमी को देखते हुए राज्य शासन ने समय रहते वैकल्पिक उर्वरकों की दिशा में ठोस पहल की। 1.86 लाख मीट्रिक टन यूरिया वितरण हेतु उपलब्ध है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यूरिया का उपयोग धान फसल में तीन बार किया जाता है। पहली बार बुवाई अथवा रोपाई के समय कुल अनुशंसित मात्रा का 30 प्रतिशत, दूसरी बार 3 से 4 सप्ताह बाद कन्से निकलने के समय एवं तीसरी बार 7 से 8 सप्ताह बाद गमेट अवस्था में किया जाता है। इस प्रकार यूरिया का उपयोग बुवाई से लेकर सिंथार तक विभिन्न अवस्थाओं में किया जाना है, जिसके अनुसार राज्य में यूरिया की

एन.पी.के. के अतिरिक्त भंडारण का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही, नैने डी.ए.पी. उर्वरक को बढ़ावा देने हेतु सहकारी क्षेत्र में एक लाख टन का भंडारण किया जा रहा है, जिससे 25 हजार मीट्रिक टन पापिकल डी.ए.पी. की आवश्यकता को पूर्ण होनी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अग्रेल माह से ही वैकल्पिक उर्वरकों के प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर फ्लैलेट तैयार कर सामान्य सहकारी समितियों एवं उपाजने केन्द्रों में प्रदर्शित किए गए, डी.ए.पी. उर्वरक के स्थान पर अन्य वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। इसी कड़ी में कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान एन.पी.के., सुपर फॉस्फेट एवं नैने डी.ए.पी. के वैज्ञानिक उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुशल प्रबंधन कर खरीफ 2025 में उर्वरकों की निष्ठा आपूर्ति की जा रही है।

महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. एकता चव्हेर, एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर का भंडारण किया जा रहा है, जिससे 25 हजार मीट्रिक टन पापिकल डी.ए.पी. की आवश्यकता को पूर्ण होनी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अग्रेल माह से ही वैकल्पिक उर्वरकों के प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर फ्लैलेट तैयार कर सामान्य सहकारी समितियों एवं उपाजने केन्द्रों में प्रदर्शित किए गए, डी.ए.पी. उर्वरक के स्थान पर अन्य वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। इसी कड़ी में कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान एन.पी.के., सुपर फॉस्फेट एवं नैने डी.ए.पी. के वैज्ञानिक उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुशल प्रबंधन कर खरीफ 2025 में उर्वरकों की निष्ठा आपूर्ति की जा रही है।

महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. एकता चव्हेर, एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर का भंडारण किया जा रहा है, जिससे 25 हजार मीट्रिक टन पापिकल डी.ए.पी. की आवश्यकता को पूर्ण होनी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अग्रेल माह से ही वैकल्पिक उर्वरकों के प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर फ्लैलेट तैयार कर सामान्य सहकारी समितियों एवं उपाजने केन्द्रों में प्रदर्शित किए गए, डी.ए.पी. उर्वरक के स्थान पर अन्य वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। इसी कड़ी में कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान एन.पी.के., सुपर फॉस्फेट एवं नैने डी.ए.पी. के वैज्ञानिक उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुशल प्रबंधन कर खरीफ 2025 में उर्वरकों की निष्ठा आपूर्ति की जा रही है।

महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. एकता चव्हेर, एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर का भंडारण किया जा रहा है, जिससे 25 हजार मीट्रिक टन पापिकल डी.ए.पी. की आवश्यकता को पूर्ण होनी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अग्रेल माह से ही वैकल्पिक उर्वरकों के प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर फ्लैलेट तैयार कर सामान्य सहकारी समितियों एवं उपाजने केन्द्रों में प्रदर्शित किए गए, डी.ए.पी. उर्वरक के स्थान पर अन्य वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। इसी कड़ी में कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान एन.पी.के., सुपर फॉस्फेट एवं नैने डी.ए.पी. के वैज्ञानिक उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुशल प्रबंधन कर खरीफ 2025 में उर्वरकों की निष्ठा आपूर्ति की जा रही है।

मरीज के लिये वह हर पल कीमती था, डॉक्टरों ने समय से लड़ी जंग- जिंदगी को मिला नया सवेरा

बेहद नाजुक स्थिति से मुक्त होकर स्वस्थ हुई रानी, डॉक्टरों की अथक मेहनत और सेवा को सराहा परिवार ने

कोरबा अम्बिकावाणी - जहाँ एक ओर चिकित्सा जगत में कुछ नकारात्मक घटनाएँ चिकित्सकों को असहज महसूस करा रही हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों की जान बचाने का जज्बा उन्हें कमजोर नहीं पड़ने देता। न्यू कोरबा हास्पिटल (एनकेएच) में एक बेहद गंभीर मामले में यही जज्बा काम आया और टीम वर्क ने उस मरीज को नया जीवन दिया, जिसकी जान पूर्ण रूप से संकट में थी। जीवन-मृत्यु से संघर्षरत मरीज को मिला नया जीवन कोलकाता निवासी एक चिकित्सक की २८ वर्षीय पत्नी रानी (बदला हुआ नाम) जमनीपाली स्थित अपने मायके आई हुई थीं। २ जुलाई की रात करीब २ बजे रानी की अचानक पेट में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गईं। उन्हें तत्काल जमनीपाली के एक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद न्यू कोरबा हास्पिटल रेफर कर दिया गया। एनकेएच पहुँचने पर रानी की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। उनका ब्लड प्रेशर (बीपी) नहीं था, शरीर में कोई हलचल नहीं थी, केवल हृत्स चल रही थी। जांच के बाद पता चला कि थैली फटने के कारण पेट में



काफी खून जमा हो गया था, जिसे रज्जई एक्स्टोपिक कहा जाता है। मरीज पूरी तरह से शॉक में थी। रानी के पति उस समय शहर से बाहर थे। डॉ. एकता चव्हेर के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने परिजनों को पूरी स्थिति समझाने के बाद तुरंत इलाज शुरू किया। सुबह तक सर्जरी कर पेट में जमे हुए खून को बाहर निकाला गया। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण रानी को सात यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। शरीर में कमजोरी के चलते उन्हें बेन में इंटका भी आ चुका था। डॉक्टर की इस टीम ने किया सफल ऑपरेशन और कुशल देखभाल

महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. एकता चव्हेर, एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर का भंडारण किया जा रहा है, जिससे 25 हजार मीट्रिक टन पापिकल डी.ए.पी. की आवश्यकता को पूर्ण होनी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अग्रेल माह से ही वैकल्पिक उर्वरकों के प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर फ्लैलेट तैयार कर सामान्य सहकारी समितियों एवं उपाजने केन्द्रों में प्रदर्शित किए गए, डी.ए.पी. उर्वरक के स्थान पर अन्य वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। इसी कड़ी में कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान एन.पी.के., सुपर फॉस्फेट एवं नैने डी.ए.पी. के वैज्ञानिक उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुशल प्रबंधन कर खरीफ 2025 में उर्वरकों की निष्ठा आपूर्ति की जा रही है।

महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. एकता चव्हेर, एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर का भंडारण किया जा रहा है, जिससे 25 हजार मीट्रिक टन पापिकल डी.ए.पी. की आवश्यकता को पूर्ण होनी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अग्रेल माह से ही वैकल्पिक उर्वरकों के प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर फ्लैलेट तैयार कर सामान्य सहकारी समितियों एवं उपाजने केन्द्रों में प्रदर्शित किए गए, डी.ए.पी. उर्वरक के स्थान पर अन्य वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। इसी कड़ी में कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान एन.पी.के., सुपर फॉस्फेट एवं नैने डी.ए.पी. के वैज्ञानिक उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुशल प्रबंधन कर खरीफ 2025 में उर्वरकों की निष्ठा आपूर्ति की जा रही है।

56 पेट्रोल पंपों में स्थापित होंगे प्रदूषण जांच केन्द्र

रायपुर। राज्य में वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण को प्रभावी बनाने की दिशा में परिवहन विभाग ने एक अहम पहल की है। आगामी दिनों में 56 पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केन्द्र की स्थापना की जाएगी। परिवहन विभाग के सचिव एवं परिवहन आ्युक्त श्री एस. प्रकाश (भाउरे)

रायपुर। राज्य में वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण को प्रभावी बनाने की दिशा में परिवहन विभाग ने एक अहम पहल की है। आगामी दिनों में 56 पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केन्द्र की स्थापना की जाएगी। परिवहन विभाग के सचिव एवं परिवहन आ्युक्त श्री एस. प्रकाश (भाउरे)

रायपुर। राज्य में वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण को प्रभावी बनाने की दिशा में परिवहन विभाग ने एक अहम पहल की है। आगामी दिनों में 56 पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केन्द्र की स्थापना की जाएगी। परिवहन विभाग के सचिव एवं परिवहन आ्युक्त श्री एस. प्रकाश (भाउरे)

सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। देश में सोयाबीन की लगभग 55 प्रतिशत पैदावार मध्य प्रदेश में होती है। वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन क्षेत्रफल 5,69,000 हेक्टेयर तथा पैदावार 62,80,600 टन थी। पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन एवं उत्पादकता में गिरावट दर्ज की गयी है।

सोयाबीन उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण सोयाबीन की बुवाई के बाद वर्षा की अनियमितता है। क्योंकि सोयाबीन एवं खरीफ की अन्य दलहनी फसलों का अंकुरण एवं पौधों की वृद्धि अधिक वर्षा से प्रभावित होती है। कुछ दिन फसल वृद्धि के दौरान वर्षा न होने से फसल को नुकसान होता है। बुवाई के तुरंत बाद अधिक वर्षा होने से भी यह नुकसान कुछ प्रतिशत से लेकर कभी-कभी बिल्कुल अंकुरण न होने तक भी हो सकता है। अतः बुवाई के बाद बीज को अधिक या कम वर्षा की स्थिति में खाना अतिआवश्यक है। बुवाई के बाद बीज



रेज्ड बेड प्लान्टर से सोयाबीन बोने के फायदे

को बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा रिज फरो पद्धति विकसित की गयी है। इस पद्धति द्वारा बुवाई करने से अधिक वर्षा की स्थिति में जल नालियों द्वारा बाहर निकल जाता है तथा सूखा दौर में नालियों में एकत्रित जल फसलों की जड़ों में मिलाने से नुकसान कम होता है।

सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। देश में सोयाबीन की लगभग 55 प्रतिशत पैदावार मध्य प्रदेश में होती है। वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन क्षेत्रफल 5,69,000 हेक्टेयर तथा पैदावार 62,80,600 टन थी। पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन एवं उत्पादकता में गिरावट दर्ज की गयी है। सोयाबीन उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण सोयाबीन की बुवाई के बाद वर्षा की अनियमितता है। क्योंकि सोयाबीन एवं खरीफ की अन्य दलहनी फसलों का अंकुरण एवं पौधों की वृद्धि अधिक वर्षा से प्रभावित होती है। कुछ दिन फसल वृद्धि के दौरान वर्षा न होने से फसल को नुकसान होता है। बुवाई के तुरंत बाद अधिक वर्षा होने से भी यह नुकसान कुछ प्रतिशत से लेकर कभी-कभी बिल्कुल अंकुरण न होने तक भी हो सकता है। अतः बुवाई के बाद बीज को अधिक या कम वर्षा की स्थिति में



बचाना अतिआवश्यक है। बुवाई के बाद बीज को बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा रिज फरो पद्धति विकसित की गयी है। इस पद्धति द्वारा बुवाई करने से अधिक वर्षा की स्थिति में जल नालियों द्वारा बाहर निकल जाता है तथा सूखा दौर में नालियों में एकत्रित जल फसलों की जड़ों में मिलाने से नुकसान कम होता है।

रेज्ड बेड निर्माण की मशीनें

रेज्ड बेड के निर्माण एवं बीज बोने के लिए बाजार में विभिन्न प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर चालित रेज्ड बेड प्लान्टर, रोटावेटर कम रेज्ड बेड प्लान्टर एवं रेज्ड बेड सीड ड्रिल के द्वारा रेज्ड बेड बनाने के साथ-साथ आसानी से बुवाई भी हो जाती है। कर्मशालाओं में परम्परागत रूप से उपयोग की जाने वाली सीड ड्रिल में रिज फरो अटैचमेंट आसानी से लगवाया जा सकता है। सोयाबीन एवं अन्य दलहनी फसलों के लिए रथानी बाजारों में विभिन्न

रेज्ड बेड के प्रकार

बेड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, चौड़े रेज्ड बेड एवं साक्रे रेज्ड बेड चौड़े रेज्ड बेड का निर्माण सामान्यतः कारी मिट्टी में किया जाता है। चौड़े रेज्ड बेड की नियाली साक्रे 1.5 से 2 मी. तथा ऊपरी साक्रे 1 से 1.5 मी. होती है। इनकी ऊपरी 1.5 से 2 मी. होती है। चौड़े रेज्ड बेड पर एक साक्रे 4 से 5 कतारों की बुवाई की जा सकती है। चौड़े रेज्ड बेड रथाई प्रकार के भी बनाये जाते हैं। रथाई चौड़े रेज्ड बेड में मोड़ एवं नाली फसल की कटाई तक बनी रहती है। इसका उपयोग कई वर्षों तक ज़ीरो टिल पद्धति के साथ किया जा सकता है। साक्रे रेज्ड बेड का निर्माण सामान्यतः रेतीली या लाल मिट्टी में किया जाता है। साक्रे रेज्ड बेड की नियाली साक्रे लगभग 0.9 मी. तथा ऊपरी साक्रे लगभग 0.1 मी. होती है। इनकी ऊपरी 1.5 से 2 मी. होती है।



रेज्ड बेड पद्धति के लाभ

- रेज्ड बेड पद्धति उपयोग करने के ये लाभ हैं—
- बुवाई के तत्काल बाद अधिक वर्षा से अंकुरण अधिक प्रभावित नहीं होता है।
- इस पद्धति में बीज का प्रयोग 10 से 15 प्रतिशत कम होता है।
- खरपतवारों का नियंत्रण हस्तचालित हेण्ड खील-हो, स्वचालित यांत्रिक बीकर या ट्रैक्टर चालित गिर्वाई यन्त्र द्वारा किया जा सकता है।
- रेज्ड बेड पद्धति में उपजती फसलों में खरपतवारों की गिराई यांत्रिक विधि से कर सकते हैं।
- रेज्ड बेड पद्धति से बुवाई करने पर फसल उत्पादन में 1.5 से 2.0 प्रतिशत तक की वृद्धि होती है।
- इस पद्धति में कम वर्षा की स्थिति में जल संरक्षण नालियों द्वारा होता है।
- रेज्ड बेड प्लान्टर से सोयाबीन के अलावा गेहूँ, मटर, चना, मूँगफली, मका एवं अन्य फसलों की बुवाई भी की जा सकती है।

रेज्ड बेड पद्धति के लाभ

- रेज्ड बेड पद्धति उपयोग करने के ये लाभ हैं—
- बुवाई के तत्काल बाद अधिक वर्षा से अंकुरण अधिक प्रभावित नहीं होता है।
- इस पद्धति में बीज का प्रयोग 10 से 15 प्रतिशत कम होता है।
- खरपतवारों का नियंत्रण हस्तचालित हेण्ड खील-हो, स्वचालित यांत्रिक बीकर या ट्रैक्टर चालित गिर्वाई यन्त्र द्वारा किया जा सकता है।
- रेज्ड बेड पद्धति में उपजती फसलों में खरपतवारों की गिराई यांत्रिक विधि से कर सकते हैं।
- रेज्ड बेड पद्धति से बुवाई करने पर फसल उत्पादन में 1.5 से 2.0 प्रतिशत तक की वृद्धि होती है।
- इस पद्धति में कम वर्षा की स्थिति में जल संरक्षण नालियों द्वारा होता है।
- रेज्ड बेड प्लान्टर से सोयाबीन के अलावा गेहूँ, मटर, चना, मूँगफली, मका एवं अन्य फसलों की बुवाई भी की जा सकती है।

कहते हैं कि पानी सरीखा दोस्त नहीं तो दुश्मन भी नहीं। जहां मरणासन्न व्यक्ति में पानी प्राण ला देता है और जन जीवन का यह आधार है वहीं पानी की अधिकता कभी-कभी उसकी तबाही का कारण भी बन जाती है। पानी के संबंध में यही बात फसलों के साथ भी लागू होती है।

जल निकासी जरूरी



फसल उत्पादन का मूल आधार पानी ही है परंतु आवश्यकता से इसकी अधिकता फसलों के लिए न केवल हानिकारक होती है बल्कि भूमि की संरचना को बिगाड़ कर चरो फसल उपयुक्त हो नहीं रहने देती है। जल निकास बंध विधि है जिसमें पौधों की पवित्र पद्धि के लिए फाइनम वॉटर से चरों के अतिरिक्त पानी को भूमि की सतह अथवा अंतःसतह से बाहर निकाला जाता है।

पानी की इस अधिकता से फसलों को कैसे बचाया जाये गरी उपाय यहां दिये गये हैं—

जल से हानियां

जल निकास के उचित प्रबंध के अभाव में खरीफ मौसम में मिट्टी के अंदर अत्यधिक नमी

हो जाती है इस आवश्यकता से अधिक नमी के कारण वर्षाकालीन फसलों एवं मिट्टी को अनेकों हानियां होती हैं।

- भूमि में वायु संचार रुक जाता है।
- मिट्टी तथा गिर जाता है।
- मिट्टी जीवाणुओं के कार्य में बाधा पड़ती है।
- पौधों की जड़ें डबली रह जाती हैं एवं सह जाती हैं।
- भूमि की भौतिक दशा में परिवर्तन हो जाता है।
- पौधों के खास पत्राणों में कमी आ जाती है।
- लवणों का मिट्टी की ऊपरी सतह पर जमाव हो जाता है।
- युवाई बुवाई आदि कृषि क्रियाएं बाधित हो जाती हैं।
- बीजों का देर से जमाव एवं फसल की गहवार रुक जाती है।
- रोग, कीट एवं खरपतवार का मध्यम आक्रमण होता है।

हल्की मिट्टी की अपेक्षा भारी, चिकनी, चिकनी दोमट भूमि में जल निकास की अत्यधिक आवश्यकता होती है क्योंकि इनमें पानी का रजाम अच्छा नहीं होता है जिससे रातों रात पानी मरा रहता है। अतः जल निकास के लिए जल निकास नालियां का निर्माण करना पड़ता है। यह जल निकास नालियां अपनी आवश्यकतानुसार गूँघी की ऊपरी सतह पर खुली नाली अथवा भूमि के अंदर अथवा सतह पर नाली बनाई जाती है। प्रायः जल निकास की दो विधियां अपनाई जाती हैं।

पृथ्वीय जल निकास

भारतीय कृषकों के लिए यह विधि अति सरल है। इसमें भूमि की किस्म, भूमि की ढाल, पानी की अधिकता आदि बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकता अनुसार दूरी पर खेत की सतह पर खुली हुई नाली खोव देते हैं जिनमें होकर बरसत का पानी खेत से बाहर निकल जाता है। यह नाली खेत की सतह पर प्राकृतिक ढाल को देखते हुए खेत की सतह पर 30 सेमी चौड़ी बनाते हैं जिनकी मेड़ 7.5 सेमी चौड़ी रखते



अधो पृथ्वीय जल निकास

जिन स्थानों पर जल स्तर उच्च रह जाने के कारण भूमि के मूल क्षेत्र में पानी मरा रहता है वहां भूमिगत जल निकास नालियां बनानी पड़ती हैं। यह जल निकास नालियां मुख्य रूप से बनाने के (ढकने के) आधार पर लकड़ी, पत्थर, टाइल तीन प्रकार की होती हैं। मिट्टी की अधो सतह में 25-30 मीटर के आपसी अंतराल पर खेत के प्राकृतिक ढाल को देखते हुए समान से 1 मीटर की गहराई में

30 सेमी चौड़ी नाली बना देते हैं जिसे लकड़ी, पत्थर या टाइल से ढककर मिट्टी से दबा देते हैं। इन नालियों में पानी के बहाव के लिए 30 मीटर दूरी पर 5 सेमी का ढाल देते हुए बनाते हैं। इस प्रकार खेत की अन्धो सतह में सहायक नालियां बना देते हैं। जिनमें सीधे उपजुक्त नालियों को मुख्य नाली से जोड़ देते हैं। जोड़ते समय ध्यान रखें कि नाली को कभी भी 90 अंश के कोण पर न जोड़ें। जल निकास में फालतू पानी प्रस्तावित होकर खेत से बाहर निकल जाता है। परिणामस्वरूप फसल पर नमी की अधिकता का कोई कुप्रभाव नहीं अंतराल पर खेत के प्राकृतिक ढाल को देखते हुए समान से 1 मीटर की गहराई में भरपूर लाभ प्राप्त हो जाता है।

